Completion of SYL Canal

805. DR. BAPU KALDATE: SHRI S. S. SURJEWALA:

WiU the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there is any plan/ proposal with the Central Government to ask the Punjab Government to complete the SYL Canal in Punjab Territory ;

(b) if so, by when the SYL Canal is proposed to be completed ; and

(c) whether any dialogue in this regard has taken place among the Central Government and the Governments of Punjab and Haryana on the issue of completion of this Canal for the benefit of small and marginal farmers in the State of Haryana ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON). (a) Government of Punjab has already been advised to engage appropriate agency/agencies to complete the balance works of SYL Canal in Punjab.

(b) The time schedule for completing the project will depend upon nature and capacity of the new agency/agencies to be engaged by Government of Punjab.

(c) In the month of July and August 1992 meetings were held with the Chief Ministers of Punjab, Haryana and Rajasthan when various inter-state water related issues were discussed. Completion of SYL Canal was one of the issues discussed daring the above meetings.

Requirement of drinking water in the Country

806. SHRI SHIV PRATAP MISHRA : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased
to state:

(a) whether it is a fact that current requirement of drinking water is 25 billion cubic metres a day;

(b) what is per capita requirement of drinking water for rural people vis-a-vis urban people;

(c) the extent to which the re quirement is met and what steps Go vernment are taking in this regard;

(d) whether it is also a fact that storing of rain water in dams, catchment area development and water harvesting are some of the measures that can meet country's damand for drinking water;

(e) if so, the measures Government propose to take in this regard;

(f) whether Government are able to provide potable water to rural people; if so, to what extent; and

(g) the reasons for shortfall ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON) : (a) to (g) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल संकट

807. श्री शांति त्यागी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल

संकट तेजी से बढ़ रहा है और लगभग एक तिहाई विकास खण्डों में जल स्तर इतना गिर गया है कि हैंडपंपों तक ने काम करना बन्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और भूगर्भ जल के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनायी गयी है ?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) भूजल स्तर के दीर्घावधिक प्रेक्षण से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में ललितपुर, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, हरदोई, सीतापुर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, बिजनौर, मुरादाबाद, लखीमपुर, खीरी, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बांदा, और प्रतापगढ़, जिलों के कुछ स्थानों में चार मीटर से अधिक की गिरावट आई है। मई, 1992 और मई, 1993 के बीच सोनभद्र और बांदा जिलों के कुछ स्थानों में भी 4 मीटर से अधिक की मौसमी गिरावट पाई गई है । जब जल स्तर पम्प की अंतर्ग्रहण क्षमता से नीचे चला जाता है तो हैंडपम्प काम करना बन्द कर देता है । ऐसा तब होता है जब पंप को जल स्तर की गिरावट की सभावना के अनुसार अधिक गहराई में नहीं लगाया जाता । केंद्रीय भूमि जल बोर्ड ने उत्तर प्रदेश सहित राज्यों में भूजल के स्तर में गिरावट को रोकने के लिए नाजुक ब्लाकों में भूजल के पुनर्भरण की स्कीम बनाई है ।

नर्मदा बांध के संबंध में पुनरीक्षण समिति की स्थापना

808. **श्री राजू भाई ए. परमार :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनुरोध पर विवादित नर्मदा बांध के मामले पर एक पुनरीक्षण समिति स्थापित करने जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बड़ोदा के शीर्षस्थ व्यक्तियों ने सरकार को पुनरीक्षण समिति की स्थापना करने के खिलाफ इस आशय का एक ज्ञापन दिया है कि इससे गुजरात राज्य क्षेत्र के लोगों के हितों पर असर पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी. के. थुंगन): (क) मध्य प्रदेश और महराष्ट्र राज्य सरकारों से नर्मदा (सरदार सरोवर) बांध के लिए पुनरीक्षा समिति की स्थापना हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) सरदार सरोवर परियोजना के लिए पुनरीक्षा समिति की स्थापना के विरुद्ध बड़ौदा और गुजरात के अन्य क्षेत्रों के लोगों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं चूंकि संघ सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए ऐसे अभ्यावेदनों के उपयुक्त उत्तर भेज दिए गए हैं ?

उत्तर प्रदेश में बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाएं

809. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या जल - संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में चल रही बड़ी और मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता प्राप्त हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और